"पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 2017-18 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल"

17 अगस्त, 2017

प्रबंधन :

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की टीम :-

- **श्री राजीव शर्मा - अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,**
- **श्री डी. रवि - निदेशक (वाणिज्यिक),**
- **श्री सी. गंगोपाध्याय - निदेशक (परियोजनाएं),**
- **श्री एन. बी. गुप्ता - कार्यकारी निदेशक (वित्त) ।**

संचालक : श्री कुणाल शाह - एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड

कुणाल शाह : हर किसी के लिए यह दिन शुभ हो । मैं एडलवाइस सिक्योरिटीज़ से कुणाल शाह हूं। आज, हमारे साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान कॉर्पोरेशन के अर्जन के बारे में चर्चा करने के लिए श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक; श्री डी. रवि, निदेशक (वाणिज्यिक); श्री गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजनाएं) और श्री गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (वित्त) उपस्थित हैं । अब अगे की कार्रवाई के लिए मैं महोदय आपको आमंत्रित करता हूं ।

राजीव शर्मा : सभी को शुप्रभात । मैं 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए हमारे वित्तीय परिणामों पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूं।

जहां तक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही (Q1) की व्यापार निष्पादन संबंधी विशेषताओं (हाइलाइट्स) का संबंध है, तो ऋण स्वीकृतियों में 47% की बढ़ोतरी हुई है और ये 34,613 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,922 करोड़ रुपए हो गई हैं। इसीप्रकार संवितरण में भी 66% की वृद्धि हुई और ये 7,754 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,849 करोड़ रुपए हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवितरण में तेज वृद्धि देखी गई और ये 236 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,200 करोड़ रुपए हो गया है । शुद्ध ऋण परिसंपत्ति में 10% की वृद्धि हुई है और ये 2,24,970 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,47,139 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार इस दौरान हमने एक मजबूत व्यवसाय विकास देखा है।

हालांकि, प्रतिस्पर्धी दबावों की वजह से बाजार में प्रचलित कम ब्याज दरों के कारण ब्याज दर में कटौती हो सकती है, इससे हमारे लाभ मार्जिन पर असर पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप, इस तिमाही के लिए हमारा लाभ पिछली तिमाही के दौरान 1,713 करोड़ रुपए की तुलना में 1,429 करोड़ रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (Q1 FY18) के लिए इंटरेस्ट स्प्रेड और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्रमशः 2.76% और 4.44% हैं। चूंकि वास्तविक ऋण बही की पहले से ही फिर से कीमत निर्धारित की जा चुकी है, इसलिए हम मौजूदा स्तरों तक विस्तार बनाए रखने की आशा करते हैं।

जहां तक परिसंपत्ति की गुणवत्ता का संबंध है, तो जैसा आप जानते हैं कि पीएफसी ने हिमालय क्षेत्र में पारेषण, वितरण, पनबिजली परियोजनाओं, जिनके लिए पीएफसी को 31 मार्च 2017 तक के लिए छूट उपलब्ध थी, को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2017 की चौथी तिमाही (Q4 FY17) में पुनर्गठन संबंधी मानदंडों को भारतीय रिजर्व बैंक

के अनुरूप पुनः संगठित किया है। पीएफसी अब सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए आरबीआई के पुनर्गठन संबंधी प्रावधानों का पालन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (Q1 FY18) के दौरान पीएफसी ने ऋण परिसंपत्तियों पर 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें से 251 करोड़ रुपए एनपीए के खाते में, मानक पुनर्गठन के मद में 95 करोड़ रुपए और मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण के मद में 46 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

जहां तक एनपीए का संबंध है, तो एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को चालू होने में देरी और लागत में 382 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण एनपीए घोषित कर दिया गया है और इसके लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । 4 वर्षों से अधिक समय तक चालू होने में देरी के कारण, जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के 2 करोड़ रुपए की राशि वाले 2 आर एंड एम ऋणों को एनपीए के रूप में घोषित कर दिया गया है, यद्यपि कर्जदार जनवरी 2010 से नियमित रूप से ऋण की किश्त दे रहा है। मौजूदा एनपीए के लिए लगभग 210 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं।

इसके साथ ही, वर्ष के लिए एनपीए अनुपात निम्नानुसार हैं: - आरबीआई के प्रभाव के साथ सकल एनपीए 12.46%, आरबीआई के प्रभाव के बिना 3.07% (पिछले वर्ष की पहली तिमाही में 3.34% की तुलना में बेहतर)। इसी तरह आरबीआई के प्रभाव के साथ शुद्ध एनपीए 10.48% और भारतीय रिजर्व बैंक के संरेखण पर आरबीआई के प्रभाव के बिना 1.81% (पिछले वर्ष की पहली तिमाही में 2.66% की तुलना में बेहतर) का सुधार हुआ है।

जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती निवेशक सम्मेलन में बताया गया है, सरकारी क्षेत्र के एनपीए के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें एमपी जेनको के ~11,000 करोड़ रुपए की राशि वाले सभी ऋणों को 15 जुलाई 2017 को अर्थात दूसरी तिमाही (Q2) में पर अपग्रेड किया गया। तीसरी तिमाही (Q3) में 7,000 करोड़ रुपए के एक अन्य ऋण को अपग्रेड किए जाने की संभावना है। इस प्रकार 31,500 करोड़ रुपए के कुल एनपीए में से 18,000 करोड़ रुपए की राशि को तीसरी तिमाही (Q3) के अंत तक अपग्रेड किया जाएगा।

जहां तक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में पहली तिमाही (Q1) में पुनर्गठित 36,505 करोड़ रुपए की राशि वाले ऋणों का संबंध है, तो इस संबंध में पहली तिमाही (Q1) में पुनर्गठन खातों में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, लगभग 1,500 करोड़ रूपए की राशि वाले एक ऋण को मानक परिसंपत्ति के रूप में अपग्रेड किया गया है। हालांकि, मौजूदा पुनर्गठित ऋण खातों में चल रहे संवितरण के कारण पुनर्गठन बही में मामूली वृद्धि हुई है।

सरकारी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के संबंध में पुनर्गठित खातों की वर्तमान स्थिति के अनुसार 36,505 करोड़ रुपए की राशि में से 62% या 22,511 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले से चालू हो चुकी हैं और वित्तीय वर्ष 18-19 में इन्हें प्रत्यावर्तित किया जाएगा । 26% या 9,530 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 17-18 में चालू होने की उम्मीद है । 12% अथवा 4,465 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 17-18 के बाद चालू होने की उम्मीद है । हम दोहराना चाहते हैं कि हमें सरकारी क्षेत्र के एनपीए और पुनर्गठित खाते में कोई दबाव नहीं दिख रहा है और इन ऋणों की नियमित रूप से किश्तें अदा की जा रही हैं।

जहां तक निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में पुनर्गठित खातों का संबंध है, तो पुनर्गठित बही में पहली तिमाही (Q1) के दौरान कमी हुई है और यह 19446 करोड़ रुपए से घटकर 18,090 करोड़ रुपए हो गई है क्योंकि एनसीसी पावर के एक खाते में 2,400 करोड़ रुपए की राशि को मानक के रूप में अपग्रेड किया गया। शिगा एनर्जी को ऋण राशि के रूप में 522 करोड़ रुपए की राशि और दी गई।

निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के संबंध में 18,090 करोड़ रुपए राशि के साथ पुनर्गठित बही की वर्तमान स्थिति 31% या 5,576 करोड़ रुपए है, जो पहले से ही चालू हो चुकी हैं, जिनमें से 4,371 करोड़ रुपए की राशि को वित्तीय वर्ष 17-18 और 1,205 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय वर्ष 18-19 में प्रत्यावर्तित की जाएगी । 64% या 11,584 करोड़ रुपए की राशि वाली परियोजनाओं की सीओडी वित्तीय वर्ष 17-18 में अधिसूचित की गई हैं।

उत्पादन परियोजनाओं की कमीशनिंग की स्थिति के बारे में दो बिन्दुओं को हाइलाइट करना चाहूंगा। हमारी कुल सकल ऋण परिसंपत्ति 2.53 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें

से उत्पादन परिसंपत्तियों के संबंध में यह 1.86 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से 1.86 लाख करोड़ की सरकारी स्वामित्व वाली परियोजनाएं 80% हैं जिनमें से 75% की कमीशनिंग पहले से ही कर ली गई है और निजी क्षेत्र की उत्पादन परियोजनाएं लगभग 20% हैं, जिनमें से 55% (एनपीए को छोड़कर) की पहले ही कमीशनिंग हो गई है। इस प्रकार 70% उत्पादन परिसंपत्तियां पहले से ही कमीशन की जा चुकी हैं।

हमारे पोर्टफोलियो के केवल 30% परियोजनाओं को कमीशन करना अभी बाकी है। जिसमें से ~57% परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 17-18 में कमीशन किए जाने की संभावना है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 70% पहले से चालू हो चुकी हैं और 16% की सीओडी वित्तीय वर्ष 17-18 में पूरी होने की संभावना है। इस प्रकार 87% उत्पादन पोर्टफोलियो या तो कमीशन किया जा चुका है या वित्तीय वर्ष 17-18 के अंत तक इसके चालू होने की संभावना है।

जहां तक संसाधन जुटाने का संबंध है, तो हमने पहली तिमाही (Q1) के दौरान महज 7% की सीमांत लागत पर लगभग 13,680 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। इसके अलावा मुझे आपको सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि पीएफसी को धारा 54ईसी के तहत पूंजीगत लाभ कर बांड जारी कर धन जुटाने की अनुमति मिल गई है और हमने जुलाई 2017 में ही पूंजीगत लाभ बांड जारी कर दिय है। हम अपने उधार पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को टैप करने की प्रक्रिया में हैं। हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात आरबीआई की 10% की आवश्यकता के मुकाबले 16.50% की टीयर 1 पूंजी के साथ आरबीआई की 15% की आवश्यकता के मुकाबले 19.54% पर होते हुए काफी अधिक/सहज है।

आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हम प्रश्न और उत्तर सत्र शुरू कर सकते हैं।

संचालक : आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हम प्रश्न और जवाब सत्र शुरू करेंगे पहला प्रश्न बजरंग बफाना की लाइन से है। कृपया आगे बोलें।

बजरंग बफाना : मैं सुनिधि सिक्योरिटीज से बजरन बफाना हुं । महोदय, क्या आप इस म. प्र. जेनको के एक्सपोज़र की व्यापक रूप से व्याख्या कर सकते हैं जो कि तिमाही के दौरान लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ अपग्रेड की जाने वाली है। क्या आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, यदि हां, तो बताएं कि यह किस

स्थिति में था और क्या हम पहली तिमाही (Q1) में या पहली तिमाही (Q1) तक इस एक्सपोजर पर ब्याज आय को मान्यता दे रहे थे या नहीं या क्या इसके आगे बढ़ने पर इसे मान्यता दी जाती रहेगी या नहीं और इस बारे में कोई अद्यतन जानकारी जैसे क्या इसे एनपीए खाते या पुनर्गठन खाते से अपग्रेड किया जाएगा जो आगे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप उन विवरणों को साझा कर सकते हैं सर?

एन बी गुप्ता : वास्तव में ब्याज से होने वाली आय की गणना हम केवल नकदी के आधार पर ही करते थे। केवल इसलिए क्योंकि यह एनपीए है और हम नकदी के आधार पर ही आय को मान्यता दे सकते हैं और ये कुल समूह के लिए एक्सपोजर है। और इसे जुलाई में अपग्रेड कर दिया गया है।

बजरंग बफाना : सर क्या यह एनपीए का हिस्सा था या फिर पुनर्गठन की गई किताब का हिस्सा था?

एन बी गुप्ता : यह एनपीए का हिस्सा था। इसलिए इस 11,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि को दूसरी तिमाही (Q2) में अपग्रेड किया जाएगा।

बजरंग बफाना : तो क्या महोदय, उन्होंने ब्याज का भुगतान किया या उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए का पूरा भुगतान किया?

एन बी गुप्ता : नहीं। 11,000 करोड़ रुपए की चुकौती का कोई सवाल ही नहीं है। ये एनपीए थे, वे समय पर सभी मूलधन और ब्याज की किश्तें अदा कर रहे थे। तो उस कमीशन के एक वर्ष के बाद, इसे अपग्रेड किया जा सकता है। तो क्या इसे दूसरी तिमाही (Q2) में अपग्रेड किया जाएगा।

बजरंग बफाना: ठीक है, सर मैं समझ गया । ब्याज से होने वाली आय को मान्यता दी जा रही थी क्योंकि वे पहले से ही ब्याज का भुगतान कर रहे थे?

एन बी गुप्ता : नकद आधार पर पहले भी मान्यता दी जा रही थी। इसे दूसरी तिमाही (Q2) के बाद से प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाएगी।

बजरंग बफाना: ठीक है, सर समझ गया । अन्य आगे किए जाने वाले अपग्रेडेशन के बारे में अद्यतन जानकारी का विवरण सर? कोई अन्य अपग्रेड जो हम इस तिमाही में उम्मीद कर सकते हैं या शायद अगली 1 या 2 तिमाहियों में किए जाने वाले हैं?

राजीव शर्मा : 6,869 करोड़ रुपए की लागत वाली छत्तीसगढ़ की एक परियोजना मारवा की क्या स्थिति है । क्या यह तीसरी तिमाही (Q3) में अपग्रेड हो जाएगी।

बजरंग बफाना: सर, यह एक बार पुन: एनपीए का एक हिस्सा है?

राजीव शर्मा : जी, हां । आरबीआई के नियमों के चलते, तकनीकी कारणों से सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं को हमें एनपीए घोषित करना होगा।

बजरंग बफाना: और क्या हम वर्तमान में ब्याज से होने वाली आय को नकद आधार पर मान्यता दे रहे हैं?

राजीव शर्मा : जी, हां।

बजरंग बफाना: तो क्या वे भुगतान कर रहे हैं, आज भी वे नियमित हैं?

राजीव शर्मा : जी, हां ।

बजरंग बफाना: ठीक है। इसलिए पी एंड एल का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जहां तक एनपीए का सवाल है, तो वे इस तिमाही में 11,000 करोड़ रुपए तक और तीसरी तिमाही (Q3) में 6,98 करोड़ रुपए तक कम हो जाएंगी?

एन बी गुप्ता : प्रोद्भवन और नकद आधार पर थोड़ा अंतर है । तो 30 जून की स्थिति के अनुसार जो भी संचित हो गया था, उसकी गणना नहीं की गई है।

बजरंग बफाना: ठीक है। तो क्या इस मामले में एनआईएम पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा?

एन बी गुप्ता : जी, हां ।

बजरंग बफाना: दूसरी तिमाही (Q2) में?

एन बी गुप्ता : जी, हां ।

बजरंग बफाना: समझ गया। कोई भी अन्य खाता सर, इस मारवा के अलावा?

एन बी गुप्ता : तत्काल इन दो खातों को अपग्रेड किया जाएगा और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 30 जून की स्थिति के अनुसार 31,000 करोड़ रुपए की एनपीए में से ~18,000 करोड़ रुपए अर्थात् 50% से अधिक के एनपीए को अपग्रेड किया जाएगा।

संचालक : आपका आपका धन्यवाद। अगला सवाल एचडीएफसी म्युचुअल फंड से आनंद लढ़ा की लाइन से है। कृपया आगे बोलें।

आनंद लढ़ा : श्रीमान जी, मैं इस तिमाही में सकल एनपीए में वृद्धि के बारे में दी गई जानकारी से बंचित रह गया? क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं, जिसके चलते इस तिमाही में सकल एनपीए में वृद्धि हुई है?

राजीव शर्मा : भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभाव के साथ सकल एनपीए 12.46% और आरबीआई के अनुरूप परिशोधन के प्रभाव के बिना 3.07% है । इसमें पिछली पहली तिमाही (Q1) में 3.34% से सुधार हुआ और आरबीआई के प्रभाव के साथ शुद्ध एनपीए 10.48% और आरबीआई के अपुरूप परिशोधन के प्रभाव के बिना 1.81% का सुधार हुआ। इसमें पिछले वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में 2.66% से सुधार हुआ है।

आनंद लढ़ा : और सर तो कुछ निजी क्षेत्र के एक्सपोजर जो इस तिमाही में एनपीए में बदल गए थे। आप एस्सार ट्रांसमिशन के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या आप इसके बारे में फिर से समझा सकते हैं?

राजीव शर्मा : यह एक ट्रांसमिशन कंपनी है, एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जिसे कमीशनिंग में विलंब और लागत में 382 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के कारण एनपीए के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमने 38 करोड़ का प्रावधान किया है।

आनंद लढ़ा : ठीक है। सर क्या यह एकमात्र खाता है जो इस तिमाही में एनपीए के रूप में बदल गया है।

राजीव शर्मा : जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम को एक छोटा सा 2 करोड़ रुपए का आर एंड एम ऋण।

आनंद लढ़ा : महोदय, एनपीए होने के बावजूद भी क्या निजी क्षेत्र में ऐसा कोई भी मामला नहीं है, जहां हमने ऑपरेशन के पुनर्गठन के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त ऋण दिया है। मैं महेश्वर परियोजना के बारे में बात कर रहा हूं सर।

राजीव शर्मा : जी, हां । हम इस परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और मानदंडों एवं शर्तों के अनुसार जो भी प्रावधान किया जाना है, हम इसे कर रहे हैं।

आनंद लढ़ा : महोदय क्या माहेश्वर के लिए कोई नया ऋण एनपीए श्रेणी में शामिल होगा महोदय?

राजीव शर्मा : जी, हां । इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और हमें 50% का प्रावधान करना होगा।

आनंद लढ़ा : तो क्या महोदय हमने इस तिमाही में महेश्वर परियोजना के लिए कोई नया ऋण दिया है?

राजीव शर्मा : 360 करोड़ रुपए।

आनंद लढ़ा : हमने उन्हें दिए हैं?

राजीव शर्मा : हमने आरएंडआर के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दिया है।

आनंद लढ़ा : ठीक है। तो क्या यह केवल सकल एनपीए का हिस्सा होगा?

राजीव शर्मा : जी, हां । तुम पूरी तरह ठीक हो।

आनंद लढ़ा : और इस पर हमें कितना प्रावधान करना पडा होगा महोदय?

राजीव शर्मा : 180 करोड़ रुपए।

आनंद लढ़ा : यही कारण है कि हमारा प्रावधान इस तिमाही में थोड़ा अधिक है । महोदय इस तिमाही के लिए हमने पी एंड एल में 112 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, क्या मैं सही हूं?

एन बी गुप्ता : ऋण परिसंपत्ति प्रावधान 392 करोड़ रुपए है। 392 करोड़ रुपए में से मौजूदा परिसंपत्तियों पर केवल 210 करोड़ रुपए है?

आनंद लढ़ा : क्या इस 210 करोड़ रुपए के एनपीए में माहेश्वर परियोजना पर 180 करोड़ रुपए का एक्सपोज़र शामिल है?

राजीव शर्मा : जी, हां ।

आनंद लढ़ा : सर आपने यह भी संकेत दिया था कि इस तिमाही में ऋण बही का पुनरीक्षण (रीप्राइसिंग) हो चुका है और इसलिए विस्तार स्थिर बने रहना चाहिए। क्या आप कुछ संकेत दे सकते हैं कि किस तरह से रिप्राइसिंग किया गया है और ऋण बही के कितने भाग के लिए ऐसा हुआ है?

राजीव शर्मा : मूल रूप से यूडीएवाई और बाजार में प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण हमें राज्य की बिजली कंपनियों, राज्य की उत्पादन कंपनियों (जेनकोस), राज्य की पारेषण कंपनियों (ट्रांसकोस) और वितरण कंपनियों (डिस्क्मों) की अपनी परिसंपत्तियों का फिर से मूल्य निर्धारण (री-प्राइसिंग) करना पड़ा । लेकिन यह पहले से ही पर्याप्त रूप से किया जा चुका है इसलिए आगे ओर री-प्राइसिंग करने के लिए अब कोई प्रस्ताव नहीं है।

आनंद लढ़ा : महोदय, हमने कितना कर लिया है सर, जैसे कि इसमें 100 आधार अंक घटाकर 50 आधार अंक घटा दिए गए हैं। क्या आप इस बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं?

एन बी गुप्ता : ऋण बही का लगभग 60%।

आनंद लढ़ा : ऋण बही के 60% ने 100 आधार अंकों की ब्याज में कमी देखी है।

राजीव शर्मा : यह निर्भर करता है। यह एक खाते से दूसरे खाते में बदलता रहता है।

आनंद लढ़ा : और महोदय, क्या आप अपने वृद्धिशील उधार उत्पादों (यील्ड) के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्या आप किसी एसईबी के जेनको को नया ऋण दे रहे हैं, तो सर उस पर क्या बढ़ोतरी हो सकती है?

राजीव शर्मा : मैंने आपको कहा था कि वास्तव में संवितरण में इस तिमाही में 66% की वृद्धि हुई थी और ऋण की मंजूरी में भी 47% वृद्धि हुई थी।

एन बी गुप्ता : देखें, हमारी सीमान्त उधारी करीब 7% है और यदि आप सामान्य औसत उधारी दर लेते हैं, तो यह 10.25 से 10.50 के आसपास आ रही है।

आनंद लढ़ा : ठीक है। इस प्रकार हम अब तक 300 आधार अंकों के ऊपरी विस्तार को बनाए रखे हुए हैं।

एन बी गुप्ता : जी, हां । सीमान्त आधार पर, सीमांत लागत।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल दाइवा कैपिटल से पुनीत श्रीवास्तव की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

पुनीत श्रीवास्तव : बेशक महोदय, आपने इन मार्जिन के बारे में चर्चा की और आपने कहा कि इस तिमाही में विस्तार और मार्जिन स्थिर होना चाहिए, लेकिन सर एक दो साल तक की लंबी अवधि में आप इस विस्तार की गति को कैसे देख रहे हैं? क्या आप उस पर कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं और वर्तमान में जो मौजूदा परियोजनाएं शुरू हो गई हैं,

उनको हासिल करने की कोशिश में बैंकों से आप किस तरह की आक्रामकता देख रहे हैं?

राजीव शर्मा : दरअसल हमारे मार्जिन पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पूंजीगत लाभ कर बांड के जरिए हमें 5.25% पर सस्ता फंड मिल रहा होगा क्योंकि इस वर्ष हमें आरईसी और एनएचएआई के अलावा पूंजीगत लाभ कर निधियां बढ़ाने के लिए भी यह अधिदेश दिया गया है। और कमीशन की जा चुकी परिसंपत्तियों का भी हम पुनर्वित्तीयन कर रहे हैं। हाल ही में, आपने देखा होगा कि हमने एनटीपीसी और यूपी के संयुक्त उद्यम वाली दो परियोजनाओं का पुनर्वित्तीयन किया है और हमने इसमें 3,700 करोड़ रुपए का संवितरण किया है। इसलिए ये सभी बैंक ही नहीं हैं, बल्कि हम भी कुछ अच्छी परियोजनाओं का पुनर्वित्तीयन कर रहे हैं, जो कि पहले ही कमीशन की जा चुकी हैं या जिनके जल्द ही चालू होने की संभावना है। इसलिए हम निकट भविष्य में हमारे मार्जिन को बनाए रखने में सक्षम होंगे।

पुनीत श्रीवास्तव : ठीक है। यह बहुत बढ़िया बात है। और महोदय इस पर मेरा एक और सवाल यह है कि क्या मैं सीएजी की इस रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता हूं, इसकी एक प्रति सीएजी की साइट पर भी पड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी व्यापक रिपोर्ट प्रदान कर दी है और यदि आप नोटिस करते हैं, तो इन खातों में से एक खाता जिसका उन्होंने उल्लेख किया है वह यह है कि केएसके, महानदी और सभी जैसे कुछ खाते जहां उन्होंने कहा है कि टैरिफ दरों और अन्य कारणों से कुछ परियोजनाएं अव्यवहार्य हो सकती हैं। तो क्या आप उन चीजों पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की 1 या 2 परियोजनाओं का ही उल्लेख किया है ।

राजीव शर्मा : मैं भी इस पर बहुत व्यापक उत्तर देना चाहूंगा। बेशक, रिपोर्ट में प्रमोटर और परियोजना दोनों के लिए अपनाई जा रही मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कुछ मुद्दों को उठाया है। हमने प्रक्रियाओं के बारे में सीएजी को विस्तार उत्तर दिया था और साथ ही साथ अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है । मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि पीएफसी की व्यापक प्रमोटर मूल्यांकन पॉलिसी को सीआरआईएसआईएल द्वारा विकसित किया गया था और प्रमोटर के अनुभव का मूल्यांकन इक्विटी फंडिंग क्षमता के संबंध में निर्धारित मानदंडों के माध्यम से किया जाता है, हम इसका मूल्यांकन पिछले संचालन, भविष्य के अनुमानों और साथ ही साथ प्रमोटरों द्वारा उठाए गए धन और कार्यान्वित की गई परियोजनाओं में इसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर करते हैं। आप इस बात की भी सराहना कर सकते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट ने पीएफसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में किसी भी वित्तीय अनियमितता को उजागर नहीं किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के संबंध में, हमने

विशेष रूप से उस विधि को बताया है जिसमें आरबीआई की शर्तों (मानदंडों) को अपनाया गया था और इसका जिकर हमारे वार्षिक लेखाओं की टिप्पणियों और निवेशक सम्मेलनों दोनों में किया गया। मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारी मूल्यांकन प्रणाली मजबूत है और इसके तीत बाजार में उपलब्ध उच्चतम मानकों का पालन किया जाता है। हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया को बिजली क्षेत्र के अन्य उधारदाताओं द्वारा बेंचमार्क के रूप में लिया जाता है।

जहां तक तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का संबंध है, तो हम तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम राज्य क्षेत्र की कंपनियों से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की संभावना की तलाश कर रहे हैं। हम प्रबंधन में बदलाव के जरिए एक परियोजना को पुनर्जीवित करने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। इस संबंध में, हम सभी हितधारकों के साथ बात कर रहे हैं। हमने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु परियोजनावार रणनीति तैयार करने के लिए 5/25, एसडीआर, एस4ए, आईबीसी और अन्य पुनर्संरचना जैसे विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए एक तनावग्रस्त परिसंपत्तियां पुनरुद्धार समूह भी बनाया है। क्या यह आपके प्रश्न का उत्तर देता है?

पुनीत श्रीवास्तव : जी, हाँ महोदय, निश्चित रूप से कुछ हद तक। इसलिए सर मैं मूल रूप से जो पूछ रहा हूं कि कुछ परियोजनाओं में मुझे नहीं पता कि क्या उन पर चर्चा करना संभव है कि उन्होंने केएसके, महानदी परियोजनाओं की व्यवहार्यता के बारे में उल्लेख किया है, तो ऐसा कुछ भी है, जहां यह परियोजना पहुंच गई है या हमें किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है?

राजीव शर्मा : हम 2-3 डेवलपर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। वे इस परियोजना को हासिल करने में रुचि रखते हैं। मैं उन पार्टियों का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन ये बहुत अच्छी पार्टियां हैं और उधारदाताओं की इन डेवलपर्स के साथ चर्चा उन्नत चरण में हैं।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल सुंदरम म्युचुअल फंड से धवल गाड़ा की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

धवल गड़ा : सर, आप जब उत्पादन के बारे में अपनी टिप्पणी कर रहे थे तो उसका एक हिस्सा मुझसे छूट गया है और आप यह समझा रहे थे कि इसमें सरकारी क्षेत्र की कितनी कंपनियां हैं और कितनी निजी क्षेत्र की हैं और उनमें से कितनी परिचालन में हैं । यदि आप बस इसे दोहरा सकते हैं, तो यह बहुत मददगार होगा?

राजीव शर्मा : निश्चित रूप से, मुझे इसे दोहराने में बहुत खुशी होगी। हमारी कुल सकल ऋण परिसंपत्ति बही 2.53 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से, उत्पादन की परिसंपत्ति 1.86

लाख करोड़ है। और इसके ब्यौरों में सरकार के स्वामित्व वाली परियोजनाएं 80% है, जिनमें से 75% पहले से ही चालू हो चुकी हैं और निजी क्षेत्र की परियोजनाएं 20% हैं, जिनमें से 55% (एनपीए को छोड़कर) पहले ही कमीशन की जा चुकी हैं। इसलिए 70% उत्पादन परिसंपत्ति पहले से ही चालू हो गई है और हमारे पोर्टफोलियो में शामिल केवल 30% परियोजनाओं को ही कमीशन करना बाकी है, जिसमें से 57% परियोजनाओं के वर्ष 2017-2018 में ही शुरू होने की संभावना है। इस प्रकार 70% परियोजनाएं पहले से ही चालू है और 16% परियोजनाओं के वर्ष 2017-2018 में चालू होने की संभावना है। इस प्रकार उत्पादन परियोजनाओं के पोर्टफोलियो की 86% परियोजनाएं या तो कमीशन हो चुकीं हैं या वर्ष 2017-2018 के अंत तक उनके चालू होने की संभावना है।

धवल गड़ा : और महोदय इस 20% में निजी और उस 55% के भीतर कमीशन की गई परियोजनाएं शामिल हैं, इस कमीशन की जा चुकी परियोजनाओं में से वास्तव में ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं, जहां कोई पीपीए नहीं है या वे स्थगित है, इसलिए क्या आप उस भाग के बारे में बता सकते हैं, जो कमीशन तो की जा चुकी हैं, लेकिन कोई पीपीए नहीं मंगाया गया था?

राजीव शर्मा : इसमें से जीएमआर छत्तीसगढ़ परियोजना है जिसमें पीपीए नहीं है। लेकिन इसके लिए हमने पहले ही एसडीआर कर दिया है और हम 2-3 राज्यों के साथ इस परियोजना को संभालने के लिए परामर्श ले रहे और बातचीत कर रहे हैं। हम राज्य क्षेत्र की बिजली कंपनियों के साथ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि परियोजना पहले से ही चालू है, यह उत्पादन भी कर रही है। इसलिए हम एक नए डेवलपर की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास 18 महीने का समय है।

धवल गड़ा : और कोई भी अन्य परियोजना जहां यह कमीशन तो हो चुकी है, लेकिन काम रुका हुआ या पीपीए नहीं है?

राजीव शर्मा : इंडियाबुल्स की नासिक परियोजना, जिसका पीपीए सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । उनके पास महाराष्ट्र वितरण कंपनी के साथ पीपीए था, लेकिन यह विवादित है इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक दृष्टि से विचाराधीन है।

धवल गड़ा : यह इंडियाबुल्स की नासिक -1 परियोजना है, है ना?

राजीव शर्मा : जी, हां ।

धवल गड़ा : कोई अन्य परियोजना सर?

राजीव शर्मा : ठीक अभी, मुझे कोई याद नहीं है क्योंकि अन्य निष्पादन के तहत हैं। इसलिए वे आंशिक रूप से प्रेषित किए जा रही हैं।

धवल गड़ा : और सर इसके भीतर क्या जोखिम होगा, तो 45% जो अभी निर्माण के अधीन है, में से आपके आकलन में ऐसी परियोजनाओं की संख्या क्या होगी, जिनको लेकर तनाव संभवतः थोड़ा अधिक हो सकता है, जहां या तो कोई पीपीए नहीं है या कुछ अन्य मुद्दे हैं और जो 20% निजी क्षेत्र के एक्सपोज़र से निर्माणाधीन हैं?

राजीव शर्मा : केएसके महानदी, लेकिन उनके पास पीपीए है । उनके पास पीपीए हैं और तीसरी इकाई की शुरुआत बहुत जल्द और आरकेएम पावर में होने की संभावना है, लेकिन उनके पास यूपी के साथ भी पीपीए हैं। यह उनकी पहली परियोजना है जहां से वे बिजली का उत्पादन और यूपी को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। फिर लैंको अमरकंटक भी है, 90% परियोजना पूरी हो चुकी है और 10% परियोजना पूर्ण होनी बाकी है।

धवल गड़ा : ठीक है । महोदय इसके अलावा कोई भी अन्य परियोजना?

राजीव शर्मा : मेरे विचार कि ये ही प्रमुख परियोजनाएं हैं। इंडियन बराथ उत्कल की पहली यूनिट चालू है और दूसरी के शीघ्र चालू होने की संभावना है। उनके पास इस पहली यूनिट के लिए टेनजोडको के साथ पीपीए उपलब्ध है।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल कोटक सिक्योरिटीज के निश्चत चव्हाठे की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

निश्चत चव्हाठे : महोदय, मेरी ओर से सिर्फ एक सवाल है और यह विकास के संबंध में है। अगर आप कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप आगे आने वाले समय में विकास को कैसे देखते हैं और इसके मुख्य चालक क्या होंगे? आपका धन्यवाद।

राजीव शर्मा : अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का वित्तपोषण, पुनर्वित्तीयन, पारेषण और वितरण क्षेत्र में उन्नत (बढ़ी हुई) वृद्धि निश्चित तौर पर प्रमुख चालक होंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही समझाया था कि पहली तिमाही (Q1) में हमारी स्वीकृतियों में 47% की वृद्धि हुई थी। और इसी प्रकार संवितरण में 66% की वृद्धि हुई थी और विशेष रूप से पहली तिमाही के दौरान, नवीकरणीय क्षेत्र के संवितरणों में पिछले साल के केवल 236 करोड़ रूपए के संवितरण की तुलना में 1,200 करोड़ रुपए की तेज वृद्धि हुई। इस साल हमने 1200 करोड़ रुपए का संवितरण किया। इस प्रकार लगभग 6 गुने की वृद्धि और अब हम अधिक की अपेक्षा करते हैं क्योंकि हम कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का पुनर्वित्तीयन करेंगे और हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नई परियोजनाओं का भी वित्तपोषण करेंगे और हमारी हिस्सेदारी पारेषण और वितरण क्षेत्र में भी बढ़ रही है।

निश्चत चव्हाठे : तो क्या आपके द्वारा जो संस्वीकृतियां दी गई होंगी, उनमें से ज्यादातर मोटे तौर पर पुनर्वित्तीयन के रूप में होती हैं, इसे हम मोटे तौर पर क्या मान सकते हैं?

राजीव शर्मा : यह लगभग 5% -10% है। लेकिन अब यह बढ़ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक एनटीपीसी और यूपी के संयुक्त उद्यम अर्थात इलाहाबाद के पास मेजा परियोजना 2 x 660 मेगावाट का पुनर्वित्तीयन किया है। हमने 17 बैंकों से इस परियोजना का अधिग्रहण किया है।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल जीएस इंवेस्टमेंट्स के श्री जी विवेक की लाइन से है। कृपया आगे बोलें।

जी विवेक : मेरी चिंता निजी क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं के बारे में थी कि उनका क्या होगा। उदाहरण के लिए, लैंको परिसमापन की ओर बढ़ रही है। हमारे एक्सपोज़र का क्या होगा? आईडीएफसी ने पहले से ही एस्सार पावर को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया है और उस विशेष एक्सपोज़र में हमारी क्या स्थिति है । और एस कुमार्स, उस परियोजना का क्या होगा, इंड-बराथ, आरकेएम के बारे में इतनी सारी चिंताएं हैं और दूसरी बात यह थी कि बिजली की खपत में बढ़ोतरी हो रही है या सौर ऊर्जा क्षेत्र थर्मल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है। और ऐसे पीपीए के बारे में क्या जानकारी है जो राज्य सरकार द्वारा सम्मानित नहीं किए जा रहे हैं?

राजीव शर्मा : आपने एक सवाल में कई सवाल पूंछ लिए हैं । तो सबसे पहले एस्सार महान हमारे लिए एनपीए है। लेकिन इस परियोजना से अच्छी खबर यह है कि इसकी दूसरी इकाई भी कमीशन की जा रही है और उनके पास पीपीए बिहार, तोरी परियोजना के साथ उपलब्ध हैं, जिसे वे इस एस्सार महान परियोजना के लिए पुनर्जीवित करने वाले हैं। दोनों इकाइयों से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसलिए परियोजना की दोनों इकाइयों के चालू होने की संभावना है। पहली इकाई पहले से ही एस्सार स्टील को बिजली की आपूर्ति कर रही है और भुगतान भी ले रही है। तो यह जानकारी एस्सार के बारे में है। आप लैंको अमरकंटक के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी दो इकाइयों के पास पहले से ही पीपीए हैं । वे उत्पादन यूनिटें हैं । एक यूनिट के पास हरियाणा के साथ पीपीए है और दूसरी यूनिट के पास मध्य प्रदेश के साथ पीपीए है। उनका टैरिफ बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है, यह लगभग पाथ आधार (पिटहैड) प्रकार की परियोजना और लैंको अमरकंटक की 3 और 4 इकाइयां लगभग 90% पूर्ण हैं। 10% कार्य अभी पूरा किया जाना है। इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्तमान परिदृश्य में जो भी विकल्प उपलब्ध होगा, हम इसका भी अनुसरण करेंगे। हम एक सरकारी कंपनी हैं । इसी तरह इंड-बराथ, आप इसकी पहली यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, उसके पास टैंजेडको के साथ पीपीए है। इसी तरह, आरकेएम पावर जेन के लिए, वे बिजली का उत्पादन और यूपी को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। परियोजना के पहले चरण के लिए उनके

पास पीपीए उपलब्ध है और आरकेएम को फिर से एक बहुत प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ मिल रहा है। और दूसरे चरण की पहली यूनिट भी कमीशन हो चुकी है, लेकिन वे अभी तक कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए करार कर रहे हैं। तो विभिन्न परियोजनाएं विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं, लेकिन वे बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर रहे हैं, हम तो उन्हें हल करने के लिए मेज के पार बैठे हैं और मंत्रालय के उच्चतम स्तर, विद्युत मंत्री के स्तर तक इसे उठा कर हल करने का प्रयास कर रहे है और पीपीए को फिर से खोलने के बारे में आप की चिंताओं से उन्हें अवगत करा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि विद्युत मंत्रालय सभी राज्य बिजली कंपनियों के लिए जल्द ही एक परामर्शी निदेश (एडवायज़री) जारी कर रहा है कि उन्हें किसी भी पीपीए को फिर से नहीं खोलना चाहिए क्योंकि यह एक कानूनी दस्तावेज है। तो यह विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन है जिसके बारे में मुझे सूचित किया गया है।

जी विवेक : और श्रीमान, लैंको ओडिशा, लांको विदर्भ के बारे में स्थिति क्या?

राजीव शर्मा : हम वहां नहीं हैं। दोनों परियोजनाओं में, हम वहां नहीं हैं, आरईसी वहाँ है।

जी विवेक : और महोदय, इस एनसीएलटी की कार्यवाही के परिणाम क्या होंगे और इनके तनाव वाली विद्युत परिसंपत्तियों के लिए खरीदार हैं, जैसे कि स्टील के क्षेत्र में हम बहुत सारे खरीदारों को देख रहे हैं । क्या महोदय बिजली परियोजनाओं या मानक बिजली परियोजनाओं में दिलचस्पी रखने वाले खरीदार हैं, एआरसी?

राजीव शर्मा : यह प्रक्रिया अभी शुरू की जानी है। हम भी अपनी उंगलियों को इसलिए क्रॉस रखे हुए हैं क्योंकि कम से कम एक परियोजना परिपक्व होनी चाहिए और हम सब यह जानेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और क्या बाजार में खरीदार हैं या नहीं? इस स्तर पर, यह कुछ भी बताना अपरिपक्व अर्थात समय से पहले होगा क्योंकि यहां तक कि इस बारे में मुझे भी पता नहीं है।

जी विवेक: सर एस कुमार और गैस आधारित बिजली परियोजनाओं के बारे में स्थिति क्या है, क्या हमारे पास भी कोई एक्सपोजर है और यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है?

राजीव शर्मा : हमारे पास हैं, लेकिन वे पहले से ही एनपीए हैं और हम उस परियोजना को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ परामर्श कर रहे हैं, हम आर एंड आर के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

जी विवेक : क्या यह अब केवल हमारे नियंत्रण में है, ठीक है सर, पुराने प्रमोटर अब एस कुमार्स के लिए हैं?

राजीव शर्मा : जी हां महोदय ।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल एमएसडी पार्टनर्स से श्री प्रफुल्ल कुमार की लाइन से है। कृपया आगे बोलें।

प्रफुल्ल कुमार : सर मैं सिर्फ यह समझना चाहता था, आपने कहा कि आपने केवल उत्पादन के क्षेत्रों के लिए ही एनपीए मानदंडों को संरेखित किया है। यदि आपको यह कार्रवाई करना है, तो अब बाकी बही की क्या स्थिति है, क्या आप इस संदर्भ में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि एनपीए अनुपात कैसे चलेगा?

राजीव शर्मा : हमने उत्पादन के क्षेत्रों के लिए एनपीए मानदंडों को संरेखित किया है, पुनर्गठन के लिए पहले हम विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानदंडों का अनुपालन कर रहे थे। वर्ष 2016-2017 से आगे हमने अपने पुनर्गठन संबंधी शर्तों को आरबीआई के अनुरूप संरेखित किया है। हिमालयी क्षेत्र में पारेषण, वितरण और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए हमें मार्च 17 तक छूट दी गई थी। लेकिन हमने सभी परियोजनाओं के लिए अब खुद को आरबीआई की शर्तों के अनुरूप संरेखित किया है, चाहे वे निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं क्यों न हों।

प्रफुल्ल कुमार : और एनपीए को मान्यता देने के मामले में भी, अब इसे 90 दिन तक के लिए संरेखित किया जाता है ।

राजीव शर्मा : जी, हाँ, वर्तमान में इसके 4 महीने शेष हैं, तथापि, दिनांक 31.03.18 को 90 दिन होंगे।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल एचडीएफसी म्युचुअल फंड से आनंद लाढ़ा की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

आनंद लढ़ा : महोदय, आप कुछ तनावग्रस्त ऊर्जा परियोजनाओं को इंगित कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपने एस्सार, तोरी के बारे में भी संकेत दिया था । तो क्या यह परियोजना निर्माणाधीन है, यदि हां, तो क्या महोदय उस परियोजना पर कुछ भी हो रहा है?

राजीव शर्मा : तोरी में सर, हमने आज तक एक भी पाई नहीं संवितरित की है और यह मंजूरी तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। मैं यह समझा रहा था कि एस्सार महान परियोजना के लिए हम एस्सार के लोगों को पीपीए प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं, जिस पर वर्ष 2010 में बिहार डिस्काकॉम के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, उस पीपीए को तोरी परियोजना से एस्सार महान परियोजना को हस्तांतरित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि दोनों इकाइयां एस्सार महान के तहत अपना उत्पादन कर सकें। एक इकाई आज बिजली पैदा कर रही है और वे एस्सार स्टील को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। दूसरी इकाई भी इस महीने कमीशन की जा रही है, और फिर वे उस टोरी पीपीए के आधार पर बिहार को बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं।

आनंद लढ़ा : और महोदय, आपने यह भी संकेत दिया था कि कुछ खबरें ऐसी भी थीं कि विद्युत मंत्रालय कुछ तनावग्रस्त बिजली परियोजनाओं को लेने के लिए उधारदाताओं के साथ काम कर रहा है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, तो किस प्रकार की परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है और क्या उस तरफ कुछ भी हो रहा है?

राजीव शर्मा : सच कहूँ तो, मेरे पास इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हां, विद्युत राज्य मंत्रि (स्वतंत्र प्रभार) के स्तर पर, सचिव स्तर पर और अतिरिक्त सचिव स्तर पर 2-3 बैठकें ली गई हैं, लेकिन हम अभी भी विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और मंत्री जी ने भी सभी बैंकरों के साथ बैठक की थी। लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कोई ठोस समाधान नहीं दिया गया है क्योंकि हर परियोजना का अपना एक अनूठा समाधान है । यह परियोजनावार होना चाहिए। लेकिन पीएफसी में, आपकी जानकारी के लिए हमने एक तनावग्रस्त परिसंपत्ति पुनरुद्धार इकाई की स्थापना की है और यह विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से वैकल्पिक हितों, मुद्दों और समाधानों पर विचार-विमर्श करेगी और हम प्रत्येक परियोजना पर विचार विमर्श करेंगे और निर्णय लेंगे कि उस परियोजना को संशोधित करने की इष्टतम रणनीति क्या हो सकती है

आनंद लढ़ा : और सर अंत में, हमारे पास एथेना ग्रुप के भी कुछ एक्सपोज़र है और क्या उन परियोजनाओं पर कुछ भी हो रहा है सर?

राजीव शर्मा : जी, नहीं, ईस्ट कॉस्ट, जी, हाँ । ईस्ट कॉस्ट, यह आंध्र प्रदेश में 2 x 660 मेगावाट क्षमता वाली एक परियोजना है। यह करीब 1.5 साल से रुक गई है। हम इसे आंध्र प्रदेश में सौंपने की कोशिश कर रहे थे और इस बारे में हम कर्नाटक सरकार से परामर्श भी कर रहे थे। इस प्रकार हम संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम इसे किसी राज्य जेनको को सौंप दें। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आरबीआई के अनुसार बाजार में जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन विकल्पों का चुनाव करेंगे।

आनंद लढ़ा : और सर इसी समूह में एक और परियोजना है, जो एथेना झारखंड है। क्या उस परियोजना पर कुछ भी हो रहा है सर?

राजीव शर्मा : हम वहां नहीं हैं अर्थात उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल सुंदरम म्युचुअल फंड से धवल गड़ा की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

धवल गड़ा : महोदय, मेरे पास सिर्फ दो प्रकार के स्पष्टीकरण थे। एक यह था सर, हमने मोज़र बियर, अनूपपुर का भी विस्तार किया है, तो क्या यह एनपीए है? वहाँ प्रगति क्या है सर?

राजीव शर्मा : मुझे आपको यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है, अच्छा है, आपने यह प्रश्न पूछा। यह एक अच्छी परियोजना है। दोनों इकाइयों के लिए उनके पास पीपीए हैं और दूसरी यूनिट में कुछ दुर्घटना घटित हो गई थी, लेकिन अब यह उत्पादन कर रही है और दोनों इकाइयों के लिए पर्याप्त पीपीए है।

धवल गड़ा : ठीक है। तो उस पर कोई चिंता नहीं है?

राजीव शर्मा : इस परियोजना में मुझे कोई तनाव नहीं दिख रहा है।

धवल गड़ा : ठीक है। और सर एक और प्रश्न, तो वो अमरावती है सर, इसके बारे में कोई अपडेट, मुझे लगता है कि हम वहां भी मौजूद हैं। तो वहां किस प्रकार के विचार हैं?

राजीव शर्मा : महाराष्ट्र इससे बिजली ले रहा है।

धवल गड़ा : इंडियाबुल्स ।

राजीव शर्मा : लेकिन इसे 25% - 30% प्लांट लोड फैक्टर पर संचालित किया जा रहा है और वे हमारे ऋण का वापस हमें भुगतान कर रहे हैं।

धवल गड़ा : ठीक है। वहाँ पर थोड़ा तनाव की संभावना है?

राजीव शर्मा : जी, हां । वहां कुछ तनाव है लेकिन हम उस पर भी समान रूप से काम कर रहे हैं।

धवल गड़ा : और सर, सिर्फ एक प्रश्न इस एस्सार पर, पिछली बार मुझे लगता है कि आपने यह कहा था कि हमारे पास महान वन के लिए एक्सपोज़र था, क्या यह सही है, जिसकी आप इस्पात संयंत्र को आपूर्ति कर रहे हैं?

राजीव शर्मा : जी, हां । हमारे पास एक्सपोजर हैं लेकिन यह पहले से ही एनपीए है।

धवल गड़ा : और सर अंत में एक और प्रश्न दूसरी श्रेणी में संवितरण के संदर्भ में, हम किस तरह की परियोजनाओं को देख रहे हैं और हम इन एक्सपोज़रों में किस प्रकार का यील्ड प्राप्त कर रहे हैं, क्या आप इस बारे में थोड़ा सा उजागर कर सकते हैं?

राजीव शर्मा : जैसे मैंने आपको बताया, हमने इस एनटीपीसी यूपी संयुक्त उपक्रम का वित्तपोषण किया, पिछले हफ्ते हमने 3,700 करोड़ का संवितरण किया। हमने 17 बैंकों से इसका अधिग्रहण किया है, यह उत्तर प्रदेश में 2 x 660 मेगावाट क्षमता वाली एक परियोजना है।

धवल गड़ा : और आपने इस पर जो निवेश किया है, उसका यील्ड क्या होगा??

राजीव शर्मा : शायद 9% के आसपास।

धवल गड़ा : ठीक है। मैं सिर्फ यह समझने की कोशिश कर रहा था साहब कि प्रारंभिक टिप्पणी में आपने उल्लेख किया कि उत्तरोत्तर यील्ड लगभग 10.2 से 10.5 है। तो मैं

आश्चर्य के साथ यह सोच रहा था कि ये किस प्रकार परियोजनाओं में से हैं क्योंकि एनटीपीसी और सभी जैसा आपने कहा कि 9% के स्तर पर हैं, तो ऑफसेट कौन कौन से हैं, जो आपको इस तरह का यील्ड हासिल करने में मदद कर रहे हैं?

राजीव शर्मा : हमारी कोष जुटाने की सीमांत लागत लगभग 7% है।

धवल गड़ा : ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है।

राजीव शर्मा : चूंकि हमारा प्रमुख वित्तपोषण राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के लिए है । यह 10% से 10.5% की सीमा में है और हम 7% के आसपास की सीमांत लागत पर निधियां जुटा रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हमार प्रसार सीमान्त लागत के आधार पर लगभग 3% है।

धवल गड़ा : और अंत में क्या यह राज्य क्षेत्र के वितरण के दायरे में आता है, है ना? मैं सिर्फ 12,800 करोड़ रुपए के भिन्न संवितरण देख रहा था, जो हमने इस तिमाही में किया था, 6000 दूसरों से आया और इसके भीतर, आपने उल्लेख किया कि इनमें से कुछ एनटीपीसी से जुड़े परियोजनाएं हैं जो 9.5% के आसपास चल रही हैं, इसलिए मैं बस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि दूसरा लाभ कहाँ किस और से आने वाला है?

राजीव शर्मा : एनटीपीसी का संवितरण हमने इस तिमाही में किया।

धवल गड़ा : यह दूसरी तिमाही, ठीक है। और महोदय पहली तिमाही (1Q) में 6,000 का जो हमने लेनदेन किया है, जो कि हमने सबसे बड़ा लेनदेन यहां किया था? दूसरे में 6,094 करोड़, जो सबसे बड़ा लेनदेन हमने यहाँ किया था, महोदय?

राजीव शर्मा : यह वास्तव में अल्पकालिक ऋण और मध्यम अवधि के ऋण हो सकते हैं, शायद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए किए गए हों। ये यूपीपीसीएल को 1,350 करोड़, आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 600 करोड़, टेंजेडको को 500 करोड़ रूपए हैं।

धवल गड़ा : और ये सभी 10% से 10.5% के बीच के यील्ड हैं जैसा आपने कहा?

राजीव शर्मा : जी, हां ।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल यूटीआई मुचुअल फंड से अमित प्रेमचंदानी की लाइन से है । कृपया आगे बोलें।

अमित प्रेमचंदानी : सर इंडियाबुल्स नासिक परियोजना की स्थिति क्या है जिसे आपने वित्तपोषित किया होगा, यह अभी भी प्रदर्शन कर रही है या वर्गीकृत है?

राजीव शर्मा : यह कमीशन हो चुकी है। लेकिन इसका पीपीए सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । इसलिए हम इस परियोजना पर काम कर रहे हैं ताकि इसे तनाव से हटाया जा सके। हम राज्य सरकार के साथ परामर्श भी कर रहे हैं।

अमित प्रेमचंदानी : और अब इस परियोजना के वर्गीकरण की स्थिति क्या है?

राजीव शर्मा : अब तक, यह मानक पुनर्संरचना है।

अमित प्रेमचंदानी : ठीक है। और इस परियोजना में आपका एक्सपोज़र लगभग 3,000 करोड़ रुपए होगा?

राजीव शर्मा : जी, हां ।

अमित प्रेमचंदानी : और आपके उत्पादन के एक्सपोज़र के संदर्भ में, इस वर्गीकरण के कितने प्रतिशत के रूप में उत्पादन के लिए है जैसे कि 185000 करोड़ रुपए के ऋण को वास्तव में शुद्ध आईडीसी के रूप में बुक किया जाएगा और मूल रूप से ब्याज जमा ऋण के रूप में परिलक्षित होगा? इसलिए जब भी कोई परियोजना डीसीसीओ के लिए तैयार नहीं हुई है, तो सभी ब्याज को ऋण के रूप में बुक किया जाता है, है ना?

एन बी गुप्ता : हमारे पास इस का एक अलग वर्गीकरण नहीं है । यह परियोजना लागत का एक हिस्सा है। हम आईडीसी के लिए भी निधियां दे रहे हैं ।

अमित प्रेमचंदानी : तो हम बस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कई मामलों में परियोजनाओं में 3-4 साल की देरी हो रही है, तो उस परियोजना की पूंजी संरचना आईडीसी की बुकिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए यह परियोजना अप्रभावी हो सकती है या फिर भी यह संभवतः व्यवहार्य हो जाएगी, और इसलिए बैंक...

राजीव शर्मा : जी, नहीं। जैसा मैंने स्पष्ट किया था, मैं दोहराता हूँ। मेरी सकल ऋण परिसंपत्ति बुक 2.53 लाख करोड़ रुपए है। जिसमें से उत्पादन क्षेत्र की परिसंपत्ति 1.86 लाख करोड़ है। और सरकारी स्वामित्व वाली परियोजनाएं 80% हैं, इनमें से 75% पहले ही चालू हो चुकी हैं और उन सभी के पास सूचीबद्ध डिस्कॉम के साथ पीपीए हैं और प्राइवेट सेक्टर 20% है, जिनमें से 55% (एनपीए को छोड़कर) पहले ही कमीशन की जा चुकी हैं। इसलिए मेरी 70% उत्पादन पिरसंपत्तियों को पहले ही कमीशन कर दिया गया है।

अमित प्रेमचंदानी : महोदय मेरा प्रश्न यह था, कि मैं समझता हूं कि यह कमीशन हो चुकी है। लेकिन यदि यह कहें कि माना इसे 2013 में कमीशन होना था और औसत कमीशन 2015 में हुआ है, परियोजना की उस पूंजीगत लागत में दो साल का ब्याज पड़ा हुआ था, जो उस परियोजना को ब्याज चुकाने की दृष्टि से सामान्य रूप से परियोजना को अव्यवहार्य बना देगा। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस 1,85,000 रु. की राशि में ब्याज पूंजीकरण तत्व कितना है?

राजीव शर्मा : सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए यह बैलेंस शीट फंडिंग है। इसलिए यहां तक कि अगर इसमें देरी है, तो हम अपने भुगतान वापस मिलते रहेंगे। उनके पास लागत और टैरिफ हैं क्योंकि वहां सीईआरसी टैरिफ लागू है। इसलिए इसमें कोई समस्या

नहीं है, खासकर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में। कुछ मामलों में निजी क्षेत्र में हां, यह हो सकता है लेकिन उनके पास पीपीए भी हैं।

सी. गंगोपाध्याय : निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में, अगर लागत में वृद्धि के लिए हमने मंजूरी दे दी है, मूल्यांकन प्रक्रिया, लागत में वृद्धि में परियोजना की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई परियोजना व्यवहार्य नहीं है, तो लागत में वृद्धि के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं दी जाती है। इसलिए मूल परियोजना लागत के एक भाग के रूप में चलाए गए आईडीसी के साथ साथ लागत में अधिक वृद्धि का उल्लेख पहले से ही व्यवहार्यता अध्ययन में किया जाता है।

अमित प्रेमचंदानी : और सर उन परियोजना की क्या स्थिति है, जो अगली दो तिमाहियों में एनपीए से बाहर आ जाएंगे क्योंकि वे कमीशन कर रही हैं, क्या इन परियोजनाओं में कमीशन के बाद हमारे पास ब्याज रीसेट करने का खंड उपलब्ध है?

सी. गंगोपाध्याय : आप देखें, ब्याज रीसेट खंड वहां है, ब्याज रीसेट जिसकी हम पेशकश कर रहे हैं, आम तौर पर 3 साल में एक रीसेट, उसमें यह खंड शामिल होगा और सभी संवितरण ब्याज रीसेट की तारीख को रीसेट हो जाएंगे। यह इन सभी परियोजनाओं के लिए हमारे मानक निबंधन और शर्तों में शामिल हैं।

अमित प्रेमचंदानी : तो जैसे ही वे कमीशन हो जाती हैं, ब्याज नीचे की ओर संशोधित हो जाता है या फिर यह 3 साल की अवधि के भीतर होता है?

सी. गंगोपाध्याय : यद्यपि यह ब्याज के नीचे या ऊपर होन से नहीं जुड़ा है। वहां ब्याज रीसेट की एक तारीख है। सभी संवितरणों को एक निश्चित तिथि पर रीसेट कर दिया जाएगा और फिर हर 3 साल में ब्याज रीसेट किया जाएगा। क्या ब्याज दर वास्तव में कम हो जाएगी, जो रेटिंग इत्यादि सहित इतनी सारी चीजों पर निर्भर करेगा जो की गई भविष्यवाणी की तरह नहीं हो सकते हैं।

एन बी गुप्ता : दूसरा, यह कमीशन या निर्माण से नहीं जुड़ा है। रीसेट यहां तक कि निर्माण परियोजना के लिए भी उपलब्ध है। हर 3 साल के बाद यह रीसेट किया जाता है।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल फेयर कनेक्ट से पुनीत माहेश्वरी की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

प्रभा : नमस्ते। इस तरफ से प्रभा। मेरा प्रश्न निजी क्षेत्र के निवेश (एक्सपोज़र) पर है। आपने कहा है कि विशेष रूप से इसमें 1,86,000 का एक्सपोजर है, जो कि उत्पादन के मद में है, उस 20% में से जो कि 37,200 करोड़ रुपए होता है, जो कि आईपीपी के मद में है। आपने कमीशन हो चुकी हैं और जिनका अभी तक कमीशन नहीं किया गया है के मामले में ब्यौरा दिया है। लेकिन क्या व्यवहार्यता के आधार पर आगे के ब्यौरे देना आपके लिए संभव होगा, तो क्या वहां हमारी कमीशन हो

चुकी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके पास पीपीए नहीं हैं या पीपीए पर कोई विवाद चल रहा है, और कुछ ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाएं भी हो सकती हैं जिनके पास पीपीए भी नहीं हैं। तो उस पर थोड़ी और अधिक प्रकाश डालें और यह भी बताएं कि इस 37,200 करोड़ रुपए की राशि का कितना भाग पहले से एनपीए है या फिर उसका पुनर्गठन किया गया है ताकि किसी को भी यह जानकारी हो सकें कि आज हमारे खड़े होने पर आपका आखिरी नुकसान क्या होगा?

राजीव शर्मा : 1.86 लाख करोड़ का 20% निजी निजी क्षेत्र के लिए है, जिसमें से 55% (एनपीए को छोड़कर) पहले से ही कमीशन हो चुकी हैं।

प्रभा : परन्तु इस 37,200 करोड़ में से कितनी एनपीए हैं, कितनी मानक पुनर्गठित और कितनी मानक हैं?

राजीव शर्मा : जिनके पास पीपीए नहीं हैं, वे इंड-बारथ पावर मद्रास हैं जो पहले से ही एनपीए है।

प्रभा : यदि आप इन तीनों के मूल्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं तो यह उपयोगी होगा?

एन बी गुप्ता : हम आपके पास वापस लौटेंगे।

प्रभा : मैं आपको एक ई-मेल डाल दूंगा । और आखिरकार क्या नुकसान होगा, इस बारे में आपका अर्थ है यह है कि कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को आपको हल्का करना (हेयरक्यूट्स) पड़ सकता है क्योंकि ब्याज के पूंजीकरण की वजह से बिजली की लागत काफी अधिक हो सकती है, खासकर यदि आपके पास दीर्घकालिक पीपीए नहीं है तो आप एक हानिकारक स्थिति में हैं। तो अंततः सभी निजी क्षेत्र से नुकसान कितना होगा, आप क्या सोचते हैं और इनके खिलाफ आप कितना प्रावधान कर चुके हैं?

सी. गंगोपाध्याय : देखें, हम वास्तव में घाटे के लिए उन आंकड़ों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आरबीआई के मानदंडों या एनसीएलटी प्रक्रिया के अनुसार कई परियोजनाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। आखिर में कितना नुकसान होगा जो केवल पता चलेगा जब समाधान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसलिए भविष्य का अनुमान लगाने के लिए समय नहीं आया है कि हमें कितना नुकसान उठाना पढ़ेगा। हालांकि, हम जीएमआर छत्तीसगढ़ के मामले में राज्यों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि जीएमआर छत्तीसगढ़ के मामले में हम एनएलसी और तमिलनाडु के साथ बातचीत कर रहे हैं, वे अधिग्रहण कर सकते हैं, कुछ और परियोजना के लिए भी हम संवाद कर रहे हैं। और इसलिए हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीएलटी या एनसीएलटी के बाहर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए हम तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेते तब तक इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। इससे पहले थोड़ा और समय होगा। इन सभी परियोजनाओं के समाधान के लिए

मंत्रालय सहित सभी हितधारकों की और से प्रयास चल रहे हैं। इसलिए हम इस समय पर अनुमानित नुकसान के आधार पर प्रावधान नहीं कर सकते हैं ।

प्रभा : बस महोदय मुझे लगता है कि यह बहुत मददगार है लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं, पावर परियोजना की अनुमानित हानि 70% - 80% से 10% के बीच हो सकती है और पीएफसी के पास बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन में बहुत मजबूत विशेषज्ञता है और विद्युत मंत्रालय का एक भाग होने के नाते, आपके पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। इसलिए बुद्धिमान संख्या और अच्छी तरह से विश्लेषण की गई कोई संख्या यदि पीएफसी से आती है, तो यह अधिक विश्वसनीय होगा अन्यथा सभी लोग सिर्फ सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त संख्या के आधार पर ही गणना करते रहेंगे। यदि आप अपनी प्रस्तुति में विश्लेषण के उस सेट को दे सकते हैं, तो यह बहुत उपयोगी और मददगार हो सकता है।

राजीव शर्मा : ठीक है। कृपया ई-मेल भेजें, हम आपको उत्तर देंगे।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल केआईएफएल ट्रेड कैपिटल से नितिन गांधी की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

निधी गांधी : सर मेरा प्रश्न एक पहले प्रतिभागी के प्रश्नों में से ही एक है जहां आपने निजी कंपनियों का जिक्र किया है, उल्लेख किए गए नामों में से एक नाम केएसके का था। तो मैं सिर्फ उनके वर्गीकरण, उनके एक्सपोजर की मात्रा और इसके बारे में आपका क्या विचार है, जानना चाहता था?

राजीव शर्मा : केएसके की दो इकाइयां पहले ही कमीशन की जा चुकी हैं। वे बिजली पैदा कर रही हैं, उनके पास पीपीए है, इस महीने के अंत तक तीसरी इकाई के चालू होने की संभावना है। और यह एक पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति है और हमारा एक्सपोज़र लगभग 2,900 करोड़ रुपए है और हम कुछ अच्छे डेवलपर्स, जो इस परियोजना के अधिग्रहण में रुचि रखते हैं, के साथ बातचीत के उन्नत चरण में हैं। मैं नाम का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी पार्टियां वहां मौजूद हैं। दोनों इकाइयों के पास पहले से ही पीपीए हैं वे बिजली पैदा कर रही हैं और आपूर्ति भी कर रही हैं।

निधी गांधी : मुझे लगता है कि एक्सपोज़र 3,600 था, जिसमें से 600 x 2 मेगावाट चालू हैं । एक और तीसरी इकाई 600 मेगावाट क्षमता वाली हो सकती है? और पूरे 3,600 के लिए आपका एक्सपोजर 2,900 करोड़ रुपए है?

राजीव शर्मा : जी, हां ।

निधी गांधी : तो क्या आप इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि आपने डेवलपर को इस उन्नत चरण का प्रस्ताव कैसे दिया है, जो इसका अधिग्रहण करेगा, तो क्या आप गैर कमीशन इकाई के साथ जारी रहेंगे या वे पूरी चीजें के साथ जारी रखेंगे?

राजीव शर्मा : इस पर चर्चा चल रही है कि क्या इकाई 5वीं और 6वीं यूनिट पूरी की जाएंगी या नहीं, क्योंकि इस माहौल में तब बिजली की मांग नहीं है, तो उन 5वीं और 6वीं इकाइयों को कमीशन करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। इसलिए मंत्रालय में भी चर्चा हुई कि हमें इसे आरबीआई के साथ उठाना चाहिए कि अगर चार इकाइयां शुरू हो जाती हैं और वे बिजली पैदा कर रही हैं, उन्हें पीपीए मिल गए हैं तो यह पूरी परियोजना को एनपीए घोषित करने की सलाह देना उचित नहीं होगा और यदि उस क्षेत्र में मांग नहीं है तो 5वीं और 6वीं यूनिट कमीशन करना एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है।

निधी गांधी : तो क्या अभी तीसरी यूनिट चालू होने जा रही है, ठीक है सर? फिर चौथी की क्या स्थिति है?

राजीव शर्मा : जी, हां, तीसरी इस महीने के भीतर और चौथी अगले 6-9 महीनों के भीतर ।

निधी गांधी : और क्या आपके पास 2900 करोड़ रुपए के एक्सपोजर में से प्रत्येक यूनिट के लिए अलग - अलग आंकड़े उपलब्ध होंगे या आपके पास ...

राजीव शर्मा : जी, नहीं। कुल परियोजना।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल सुभकाम वेंचर्स से स्नेहा गनात्रा की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

स्नेहा गनात्रा : सर आपने 18,000 करोड़ रुपए के बारे में उल्लेख किया है, तो क्या इसका उन्नयन हो रहा है, तो आप अपने सकल एनपीए को वित्तीय वर्ष 18 तक सुलझाने के लिए इसे कहां देख सकते हैं और क्या आप वित्तीय वर्ष 2019 के लिए कुछ भी साझा कर सकते हैं, कोई भी अपडेट, निजी के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र की परियोजना दोनों के बारे में?

एन बी गुप्ता : वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि 31 मार्च 2018 की स्थिति क्या होगी। लेकिन जो हमने आपको सूचित किया है, वह यह है कि इस वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से 18,000 को प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।

स्नेहा गनात्रा : ठीक है। अगले साल 2019 के लिए कुछ भी?

राजीव शर्मा : यह कहना कठिन हो जाएगा कि 31 मार्च 2019 की स्थिति क्या होगी।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल डोलट कैपिटल से विनोद चरी की लाइन से है। कृपया आगे बोलें ।

विनोद चारी : आपने उल्लेख किया है कि आपके पास 1.86 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। मेगावाट के संदर्भ में एक्सपोजर क्या होगा?

राजीव शर्मा : 89,790 मेगावाट ।

विनोद चारी : और सर, आपने उल्लेख किया है कि इस का 20% मानक संपत्ति होगी, क्या मैं सही हूं?

राजीव शर्मा : जी, नहीं, 20% निजी क्षेत्र के लिए है।

विनोद चारी : ठीक है। और मेगावाट के संदर्भ में मानक संपत्ति क्या होगी?

राजीव शर्मा : इस बारे में हम वापस लौटेंगे।

विनोद चारी : ठीक है। और महोदय अभी की स्थिति के अनुसार प्रणाली की समग्र मानक संपत्ति क्या है? मेरा मतलब है कि अगर आप पीएफसी बैंकों और अन्य वित्तपोषण एजेंसियों को भी शामिल कर लेते हैं, तो ।

एन बी गुप्ता : देखें, हमारे पास 2.53 लाख करोड़ के बुक आकार में से 31,000 करोड़ रुपए का कुल एनपीए है।

विनोद चारी : लेकिन क्या यह मेगावाट के संदर्भ में भी इसी प्रकार समान होगा या?

एन बी गुप्ता : जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

सी. गंगोपाध्याय : उत्पापदन में पूरी चीजें नहीं हो सकती हैं। इसलिए केवल उत्पादन परियोजना के लिए ही भौतिक इकाई मेगावाट होगी लेकिन हमारे पास टी एंड डी परियोजनाएं भी हैं जो मेगावाट के संदर्भ में परिभाषित नहीं जाती हैं ।

विनोद चारी : जी, नहीं। मैंने सोचा था कि जब आप 2.53 लाख करोड़ का उल्लेख करेंगे, तो मैंने सोचा था कि उत्पादन के लिए 1.86, बाकी पारेषण और वितरण के लिए होगा।

सी. गंगोपाध्याय : इसमें, निश्चित रूप से कोई भी गणना कर सकता है।

विनोद चारी : देखो, मैं आपके द्वारा वित्त पोषित किए गए 89,000 मेगावाट के बारे में जानना चाहता था, इसका कितना भाग मानक है और सिस्टम में समग्र मानक परिसंपत्ति क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न नवीनीकरण पर है, आपने शुरुआत में उल्लेख किया है कि आपका नवीकरणीय संवितरण 1,200 करोड़ रुपए था। इन परियोजनाओं के लिए औसत पीपीए क्या है?

राजीव शर्मा : यह एक परियोजना से लेकर दूसरी परियोजना तक अलग-अलग है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह सौर ऊर्जा क्षेत्र में है और एनटीपीसी या राज्य के माध्यम से इसके लिए बोली लगाई गई है।

विनोद चारी : लेकिन अगर आप हमें वह ऐसा श्रेणी, जिसमें टैरिफ गिरता है, के बारे में बता सकें, तो यह उपयोगी होगा?

राजीव शर्मा : सभी पीपीए व्यवहार्य पीपीए हैं। किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले, हम इस पर बहुत मेहनत और समझदारी से विचार करते हैं।

विनोद चारी : जरुर सर। मैं यह समझता हूँ। लेकिन क्या टैरिफ की शर्तों में कोई परिवर्तन किया गया है?

सी. गंगोपाध्याय : रेंज के बारे में 6 रु. से 3 रु. और 3.60 रु. के आस पास है। कुछ मामलों में, इसे व्यवहार्यता कैप फनडिंग का अतिरिक्त समर्थन भी मिला है। इसलिए पीपीए अलग - अलग हो सकते हैं। अब यह वास्तव में लगातार घट रही है।

राजीव शर्मा : पवन ऊर्जा में भी कहीं कहीं उत्पापदन आधारित प्रोत्साहन लागू हैं, क्या वे पूर्व परियोजनाएं हैं?

विनोद चारी : जी, नहीं, मैं नई परियोजनाओं के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे हमने पिछली तिमाही में फंडिंग की होगी।

राजीव शर्मा : वे 4 करोड़ से अधिक की रेंज में हो सकते हैं। हम कह सकते हैं 4.5-4.65 करोड़ रु.।

विनोद चारी : महोदय, इस टैरिफ के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा मतलब है कि क्या हम यूएमपीपी की तरह के टैरिफ की फिर से हैजिंग रहे हैं, क्या सौर और पवन डेवलपर्स भी उद्धृत कर रहे हैं?

राजीव शर्मा : मैं टिप्पणी नहीं कर सकता । बाजार तय करेगा।

विनोद चारी : लेकिन आप अपने पक्ष से उचित परिश्रम करेंगे, सही?

राजीव शर्मा : जी, नहीं। हमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, जहां टैरिफ 2.44 रु. है। इसलिए हमने उस प्रस्ताव को अभी तक प्राप्त नहीं किया है। इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं।

विनोद चारी : और महोदय, इस खबर के बारे में हम ये सुनते रहते हैं कि टैरिफ 3 रु., 3.5 रु., और 4 रु. तक आ गया था, राज्य अब उन शुल्कों पर पुन: मोलभाव कर रहे हैं और उन्हें कम कराने की कोशिश कर रहे हैं।

राजीव शर्मा : ये द्विपक्षीय समझौते हैं लेकिन विद्युत मंत्रालय पूरी तरह से जागरूक है और स्थिति का जायजा ले रहा है। मुझे लगता है कि वे राज्यों के लिए कुछ सलाह (एडवाइज़री) जारी करने जा रहे हैं कि उन्हें पीपीए को फिर से नहीं खोलना चाहिए।

विनोद चारी : लेकिन उस मामले में क्या होता है । अगर वहां कोई राज्य सरकार की सलाह (एडवाइज़री) है, तो वे डेवलपर को वापस जाने और टैरिफ की पुन: गणना करने के लिए कह रहे हैं, क्या उस विशेष परियोजना की क्रेडिट रेटिंग नीचे चली जाएगी, क्या आप उस परियोजना के लिए धन की अपनी लागत में वृद्धि करेंगे?

राजीव शर्मा : सौभाग्य से, हमारी परियोजनाओं जो हमने वित्तपोषित की हैं, में से कोई भी परियोजना नहीं है, जिस पर बातचीत चल रही हो।

संचालक : आपका धन्यवाद। अगला सवाल सौरभ कुमार की लाइन से है। वह व्यक्ति विशेष के रूप में एक निवेशक हैं । कृपया आगे बोलें।

सौरभ कुमार : सबसे पहले, मुझे लगता है कि अधिकांश दिए गए उत्तर एनपीए से संबंधित हैं और अंश के रूप में एनपीए के बारे में विश्लेषक के साथ वाले निवेशक भलीभंति वाकिफ हैं, लेकिन मेरे जैसे आम निवेशकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं सभी शेयरधारकों की ओर से आपके प्रति बहुत आभारी रहूंगा यदि आप एक प्रस्तुति, एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति या ग्राफ़िक प्रस्तुति को प्रस्तुत करते हुए यह बताते हैं कि एनपीए चक्र कैसे और फिर एनपीए से मानक चक्र कैसे चलता है। हमारे जैसे छोटे निवेशकों के लिए यह बहुत उपयोगी होगा।

राजीव शर्मा : जी, ज़रूर

सौरभ कुमार : और दूसरा सवाल यह था, हाल ही में लगभग 2-3 महीने पहले कुछ ऐसी खबरें थीं, आरईसी और पीएफसी का एक साथ विलय कर दिया जाएगा, क्योंकि वे उसी क्षेत्र की कंपनियां को ऋण देते हैं। तो क्या ऐसी कोई कार्यवाही चल रही है?

राजीव शर्मा : मैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हूं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को इस पर नजर रखना है । मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं।

संचालक : धन्यवाद महोदय। हम अपने अगले प्रश्न पर जाएंगे, जो जीएस इंवेस्टमेंट्स से जी विवेक की लाइन से है। कृपया आगे बोलें।

जी विवेक: इसलिए भारत वर्तमान में पिछले 70 वर्षों से एक अभूतपूर्व स्थिति में है। इसमें विद्युत की कोई कमी नहीं है। यूपी जैसे राज्यों में, ज्यादातर लोग 24 घंटों के लिए बिजली पा रहे हैं और अभी भी बिजली की कमी पीछे रह रही है। तो मूल रूप से मैं भारत में बिजली की खपत में वृद्धि के बारे में जानना चाहता था, अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, उदाहरण के लिए एसी विक्रय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं, पहले वहां कोई बिजली नहीं थी, लेकिन अब बिजली प्रचुर मात्रा में है । उस संबंध में और औद्योगिक गतिविधि के संबंध में, भारत में बिजली की खपत में बढ़ोतरी के बारे में आपका क्या विचार है महोदय?

राजीव शर्मा : भारत में प्रति व्यक्ति खपत अभी भी 1,100 यूनिट से कम है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में काफी कम है। चीन में, यह 3,000 यूनिट से अधिक है। और इसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों को दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम ज्योति योजना, आर-एपीडीआरपी, एकीकृत बिजली विकास जैसी भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से बिजली मिल रही है। भारत सरकार भी एक नई योजना लागम करने वाली है, देश के सभी परिवारों के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य के साथ । इससे अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण संभव होगा। इसलिए निश्चित रूप से बिजली की मांग बढ़ेगी और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसलिए निश्चित रूप से अधिक बिजली की खपत, अधिक घरेलू उपकरणों होंगे तो आने वाले

दिनों में, भविष्य बहुत उज्ज्वल है और अगर आप कहते हैं कि कोई यह कहता है कि प्रणाली में कोई मांग नहीं है, मांग को दबा दिया गया है क्योंकि राज्य की सत्ता हाल ही में ग्रामीण इलाकों में अधिक बिजली पंप नहीं करना चाहती क्योंकि उनके नुकसान में वृद्धि हुई है। लेकिन अब यूपी में भी वे सभी 100% उपभोक्ताओं की मीटरिंग कर रहे हैं। यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी, वे ऊर्जा लेखांकन करने में सक्षम होंगे और यदि वे ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे, 24/7 घंटे आपूर्ति करते हैं, तो वे इसे भी इकट्ठा कर सकेंगे क्योंकि अगर वे गुणवत्तायुक्त और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करते हैं, तो उपभोक्ता उसी तरह भुगतान करने के लिए तैयार हैं जैसे वे मोबाइल के लिए भुगतान कर रहे हैं।

जी विवेक: दूसरी बात यह है कि इस समय मूल रूप से जमीन प्राप्त करने के बारे में बहुत मुश्किल है। सीमेंट संयंत्रों के समान, अब इस नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आने के बाद से बिजली संयंत्रों को भी भूमि उपलब्ध हो रही है। इसलिए किसी भी नई बिजली परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध हो पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसके संदर्भ में, पूरे बिजली संयंत्रों के लिए बहुत सारे खरीदार उपलब्ध होंगे, इसलिए आज के समय में मंजूरी और भूमि अधिग्रहण बहुत मुश्किल है। इसलिए यद्यपि मानक पावर प्लांट एआरसी के लिए भी काफी व्यवहार्य हैं, उदाहरण के लिए आधुनिक पावर को एडेलवीस ने ले लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि पहली परियोजना है, जिसका अधिग्रहण किया गया। तो मौजूदा परियोजना के लिए श्रीमान जी आपका दृष्टिकोण क्या है?

राजीव शर्मा : महोदय जब प्रस्ताव हमारे पास आता है और हम इसका मूल्यांकन करते हैं, यह एक पूर्व-संवितरण की स्थिति है। जब तक जमीन वहां नहीं होगी, हम एक भी पाई का भुगतान नहीं करेंगे। इसलिए हम बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के लिए इन सभी बुनियादी चीजों को ध्यान में रखते हैं। इससे पहले कि हम किसी भी ऋण को मंजूरी दें, इसकी ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। सभी वैधानिक मंजूरी, पानी की उपलब्धता, ईंधन उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण, सभी के बारे में हम ध्यान रखते हैं और हम इस बारे में चिंता नहीं करते हैं कि इसका अधिग्रहण किया जा रहा है या नहीं। यह डेवलपर की चिंता है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि आम तौर पर जब तक ईंधन, पानी, जमीन और पीपीए की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक हम एक भी पाई संवितरित नहीं करते हैं।

सी. गंगोपाध्याय : वास्तव में, हमारे पोर्टफोलियो में किसी भी परियोजना में आज भी कोई भूमि संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम वास्तव में हमारी

स्वीकृति, संवितरण और अन्य गतिविधियों और उन सभी चीजें के रास्ते पर नहीं आ रहा है।

जी विवेक: यह ऐसा नहीं है। तो मेरा मतलब है कि यदि आज शुरू करें, तो पिछले 5 सालों से मेरा मानना है कि नए बिजली संयंत्र लगाने में ज्यादा निवेश आवश्यक नहीं है। भूमि अधिग्रहण और स्वीकृतियां और पीपीए के साथ पुराने विद्युत संयंत्र, कुछ पीपीए और पीपीए के बिना भी वे काफी व्यवहार्य हैं। उन्हें खरीदार मिल जाएंगे । तो भारत में धीरे-धीरे बिजली की खपत में वृद्धि हो रही है।

राजीव शर्मा : मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं।

सी. गंगोपाध्याय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन सभी मौजूदा लघु परियोजनाओं का भविष्य में बेहतर विकास होगा क्योंकि इस देश में जमीन का अधिग्रहण आने वाले दिनों में कठोर और कठोर हो जाएगा।

संचालक : आपका धन्यवाद। देवियो और सज्जनो, यह अंतिम प्रश्न था। मैंने अब टिप्पणियों को बंद करने के लिए सम्मेलन को श्री कुणाल शाह को सौंप दिया है।

कुणाल शाह : समय देने और भविष्य के विकास की उम्मीद के बारे में बताने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रबंधन का धन्यवाद । और सभी प्रतिभागियों का एक बार फिर इस कांफ्रेंस कॉल में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आपका सभी का धन्यवाद।

राजीव शर्मा : हमें यह अवसर देने के लिए श्री कुणाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

संचालक : आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड की ओर से इस सम्मेलन को समाप्त करता हूं।